



बाल सुरक्षा और साइबर जोखिमों पर सरकार का कड़ा रुख: इंस्टाग्राम के कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों पर मेटा से जवाब तलब, व्हाट्सएप फीचर भी जांच के दायरे में

नई दिल्ली। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सोशल मीडिया कंपनी Meta से तत्काल जवाब तलब करें। मामला इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर ऐसे विज्ञापनों के प्रसारित होने से जुड़ा है, जिनमें बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री या उससे जुड़े संदर्भ दिखाई देने के आरोप लगे हैं। सरकार यह जानना चाहती है कि ऐसी सामग्री विज्ञापन प्रणाली तक कैसे पहुंची और उसे रोकने के लिए कंपनी ने क्या सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सूत्रों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटा को औपचारिक नोटिस भेजकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांग

सकता है। सरकार यह जानना चाहती है कि इंस्टाग्राम की विज्ञापन समीक्षा प्रणाली (Ad Review System) किस प्रकार कार्य करती है, संदिग्ध या अवैध सामग्री की पहचान के लिए कौन-कौन से तकनीकी और मानवीय उपाय अपनाए जाते हैं तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में कंपनी की आंतरिक निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। इसके साथ ही मंत्रालय यह भी पूछ सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी कौन से अतिरिक्त कदम उठाते जा रही है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल तकनीकी सेवा प्रदाता नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण उपलब्ध कराना भी उनकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री या उसके प्रचार-प्रसार को लेकर सरकार शून्य



सहनशीलता की नीति अपनाने के पक्ष में है। ऐसे मामलों में समय पर पहचान, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी मॉडरेशन व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक माना जा

रहा है। गौरतलब है कि यह एक ही सप्ताह में दूसरा अवसर है जब मेटा सरकार के निशाने पर आया है। इससे पहले

नंबर के स्थान पर यूजरनेम आधारित यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि मोबाइल

नंबर के स्थान पर यूजरनेम आधारित यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि मोबाइल

नंबर के स्थान पर यूजरनेम आधारित यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि मोबाइल

नंबर के स्थान पर यूजरनेम आधारित यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका व्यक्त की थी कि यदि मोबाइल

जैश-ए-मोहम्मद का कथित नेटवर्क ध्वस्त करने का दावा: गुजरात और मध्य प्रदेश से आठ संदिग्ध गिरफ्तार, यूएपीए के तहत मामला दर्ज

अहमदाबाद। गुजरात में कथित आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विकल करने का दावा किया है। गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने एक समन्वित अभियान चलाते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आठ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में इन सभी के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए लोग संगठन के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और गुजरात में उसका नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत थे। गुजरात एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई कई दिनों तक चली खुफिया निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के बाद की गई। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारी की और आठ लोगों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपियों का उद्देश्य कथित रूप से गुजरात में संगठन का समर्थक तंत्र विकसित करना, नए लोगों को जोड़ना और भविष्य



में आतंकी गतिविधियों के लिए आवश्यक नेटवर्क तैयार करना था। फिलहाल यह जांच का जा रही है कि उनके संपर्क किन-किन लोगों से थे, उन्हें कथित रूप से किस प्रकार का मार्गदर्शन या सहायता मिल रही थी तथा उनकी गतिविधियों का दायरा कितना व्यापक था। एटीएस के अनुसार, सभी आरोपियों के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 17, 18, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन या संसाधन उपलब्ध कराने, आतंकी साजिश रचने, किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता या समर्थन तथा उससे

जुड़े अन्य अपराधों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 148 और 61 के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच का अगला चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, सोशल मीडिया गतिविधियों, डिजिटल संचार और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच कर रही हैं। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या उनके संपर्क देश के अन्य राज्यों या विदेश में मौजूद किसी व्यक्ति अथवा नेटवर्क से भी जुड़े हुए थे। साथ ही यह भी जांच की जा

रही है कि कहीं उन्हें ऑनलाइन माध्यमों से कटुपंथी विचारधारा की ओर प्रेरित तो नहीं किया गया था। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि क्या गिरफ्तार किए गए लोगों ने किसी प्रकार की भर्ती गतिविधि, प्रचार-प्रसार, धन जुटाने या अन्य व्यक्तियों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया था। यदि जांच में ऐसे कोई साक्ष्य सामने आते हैं तो मामले का दायरा और विस्तृत हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में आतंकी संगठन पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग कर समर्थकों तक पहुंचने और नए नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों अब साइबर निगरानी, डिजिटल फोरेंसिक और तकनीकी खुफिया तंत्र का अधिक व्यापक उपयोग कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। गुजरात एटीएस ने फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी होने का हवाला देते हुए अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच के दौरान अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

हर आधे घंटे में उठिए, सेहत बचाइए: लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा, नई स्टडी में बड़ा दावा

स्कॉटलैंड। आधुनिक जीवनशैली में घंटों तक लगातार बैठकर काम करना अब केवल कमर दर्द या मोटापा का कारण नहीं माना जा रहा, बल्कि यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जोखिम को भी बढ़ा सकता है। स्कॉटलैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक बड़े अध्ययन में दावा किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन वैज्ञानिक पत्रिका PLOS Medicine में प्रकाशित किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लगातार 30 मिनट या उससे अधिक समय तक बिना उठे बैठे रहते थे, उनमें कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम अपेक्षाकृत अधिक पाए गए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक ऑब्ज़र्वेशनल स्टडी है। इसका अर्थ यह है कि यह अध्ययन सीधे तौर पर यह सिद्ध नहीं करता कि केवल बैठने से ही कैंसर होता है, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने और कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध अवश्य दिखाई देता है। इसलिए इन निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश सलाह नियमित व्यायाम, जिम या तेज शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित रही हैं, लेकिन यह अध्ययन एक नया संदेश देता है। यदि कोई व्यक्ति दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करता है, तो केवल शाम को एक घंटा व्यायाम करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। पूरे दिन के दौरान हर आधे घंटे में कुछ मिनट के लिए उठकर टहलना, सीढ़ियां चढ़ना, पानी लेने जाना या हल्का-फुल्का काम करना भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं।

लगातार निगरानी रखी गई। प्रतिभागियों की दैनिक गतिविधियों का आकलन करने के लिए स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जैसे विद्यरेख उपकरणों का उपयोग किया गया, जिससे यह पता लगाया जा सका कि वे दिनभर कितनी देर सक्रिय रहते हैं और कितनी देर लगातार बैठे रहते हैं। अध्ययन का नेतृत्व डॉ. फ्रेडरिक हो और उनकी शोध टीम ने किया। शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका PLOS Medicine में प्रकाशित किए गए हैं। अध्ययन में पाया गया कि जो लोग लगातार 30 मिनट या उससे अधिक समय तक बिना उठे बैठे रहते थे, उनमें कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम अपेक्षाकृत अधिक पाए गए। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह एक ऑब्ज़र्वेशनल स्टडी है। इसका अर्थ यह है कि यह अध्ययन सीधे तौर पर यह सिद्ध नहीं करता कि केवल बैठने से ही कैंसर होता है, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने और कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध अवश्य दिखाई देता है। इसलिए इन निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश सलाह नियमित व्यायाम, जिम या तेज शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित रही हैं, लेकिन यह अध्ययन एक नया संदेश देता है। यदि कोई व्यक्ति दिनभर ऑफिस में बैठकर काम करता है, तो केवल शाम को एक घंटा व्यायाम करना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। पूरे दिन के दौरान हर आधे घंटे में कुछ मिनट के लिए उठकर टहलना, सीढ़ियां चढ़ना, पानी लेने जाना या हल्का-फुल्का काम करना भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने कुछ व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं।

उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन लगातार बैठने के एक घंटे की जगह करपाई पर प्रेस करना, बर्तन धोना, घर के छोटे-मोटे काम करना या अन्य हल्की शारीरिक गतिविधियां करता है, तो कैंसर से मृत्यु का जोखिम लगभग 12 प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसी प्रकार प्रतिदिन लगभग 30 मिनट सामान्य गति से पैदल चलना भी जोखिम को लगभग 8 प्रतिशत तक घटाने में सहायक हो सकता है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 मिनट तेज या अधिक तीव्र शारीरिक गतिविधि करता है, तो यह जोखिम लगभग 22 प्रतिशत तक कम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अध्ययन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय तक कार्यालयों में कंप्यूटर पर काम करते हैं, ऑनलाइन बैठकों में लगातार शामिल रहते हैं या घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) के दौरान कई घंटों तक अपनी सीट से नहीं उठते। ऐसे लोगों के लिए छोटी-छोटी गतिविधियां भी दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती हैं। भारत में भी इस विषय को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजिज इन्फेक्शंस एंड रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में किसी न किसी प्रकार के कैंसर का खतरा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही गतिहीन जीवनशैली, यानी लंबे समय तक बैठकर काम करना और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि का अभाव, कैंसर के बढ़ते मामलों के प्रमुख कारणों में शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक बैठे रहने की आदत विशेष रूप से आंत

(कोलोरेक्टल) कैंसर और गर्भाशय (एंडोमेट्रियल) कैंसर जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ाने से जुड़ी पाई गई है। इसके अलावा मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याओं में भी शारीरिक निष्क्रियता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आईसीएमआर का अनुमान है कि भारत में लगभग 70 प्रतिशत कैंसर मामलों को रोक जा सकता है, क्योंकि उनका संबंध तंबाकू सेवन, असंतुलित आहार, मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता जैसे परिवर्तनीय जोखिम कारकों से है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आपका काम लंबे समय तक बैठकर करने वाला है, तो हर 30 मिनट पर कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए अपनी सीट से उठें। थोड़ी देर टहलें, स्ट्रेचिंग करें, पानी पीने जाएं या हल्की गतिविधि करें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करना, छोटी दूरी पैदल तय करना और दिनचर्या में नियमित व्यायाम शामिल करना भी लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है। हालांकि इस अध्ययन के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि कैंसर एक जटिल बीमारी है, जिसके पीछे आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली से जुड़े अनेक कारण होते हैं। इसलिए केवल लंबे समय तक बैठना ही कैंसर का प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जा सकता। फिर भी उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि सक्रिय जीवनशैली अपनाकर, नियमित शारीरिक गतिविधि करना और लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचना न केवल कैंसर बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।



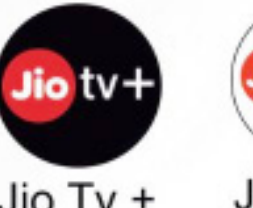
गरवी गुजरात हिन्दी



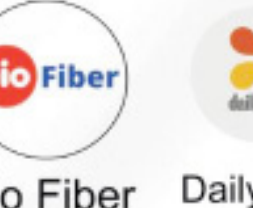
JioTV CHENNAL NO. 2002



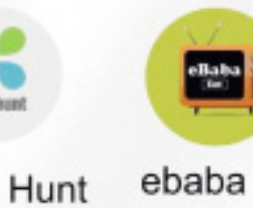
Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

इथेनॉल का मोल

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जुझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फलेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल, ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियों ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खांमियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा संकटलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं।

निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरें चढ़ाने के लिए बहुत सौच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे काफी बड़े तामाग फायदों को साबित किया है। इससे हमारे विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां हैं। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने ईंधन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं। निस्पंदेह, इन मुद्दों को सीधे खारिज करने के बजाय इन पर गंभीर रूप से मंथन करना चाहिए। अगर इन मुद्दों का निराकरण नहीं होता है तो भ्रम व संशय की स्थिति बनी रहेगी। जिसे अविचार्य दूर करने की भी जरूरत है। इस वैकल्पिक ईंधन की सहज उपलब्धता के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर व गाड़ियों को इसके अनुरूप बनाना, वैकल्पिक ईंधन की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण तथा इससे जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बाॅयोफ्यूल इतनी जल्दी फॉरिलत फ्यूल का विकल्प नहीं बन सकता। इस बाबत पर्याप्त तैयारी, पारदर्शिता और सभी हितधारकों का सहयोग लेना जरूरी है। इस मामले में जल्दबाजी करने से बचा जाना चाहिए। यदि हम सजगता व सतर्कता से आगे बढ़ते हैं तो ई-85 एक सफल मॉडल बन सकता है। अन्यथा हम एक अच्छा मौका चूक सकते हैं।

अभियान

जहां हर गली में बसती है आस्था और हर मंदिर सुनाता है हजारों वर्षों का इतिहास

भारत की पहचान केवल उसकी विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं से ही नहीं, बल्कि उसकी प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से भी है। इस देश के कोने-कोने में ऐसे अमूल्य धर्म, मंदिर और ऐतिहासिक नगर बसे हुए हैं, जो सदियों से लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। उतर में हिमालय की गोद से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक भारत का हर क्षेत्र कहीं न किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व को अपने भीतर समेटे हुए है। यहीं कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत आध्यात्मिक पर्यटन के सबसे बड़े केंद्रों में गिना जाता है। यहां आने वाले पर्यटक केवल प्राकृतिक सुंदरता देखने नहीं आते, बल्कि वे उस संस्कृति, दर्शन और जीवनशैली को महसूस करना चाहते हैं, जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी है। दक्षिण भारत का प्राचीन नगर कांचीपुरम ऐसा ही एक अद्भुत स्थान है, जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास स्वयं जीवंत होकर हमारे सामने खड़ा हो।

तमिलनाडु राज्य में स्थित कांचीपुरम भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। इस शहर का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों से भी अधिक पुराना बताया जाता है। प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक अभिलेखों और पुरातात्विक प्रमाणों में इस नगर का उल्लेख बार-बार मिलता है। कभी यह फुल्लव का इतिहास प्रसिद्ध को राजधानी हुआ करता था और बाद में चोल, विजयनगर तथा अन्य

भाई-बहन की जोड़ी मोदी-ताकाइची ने रचा इतिहास

हिंद प्रशांत में संतुलन की नई धुरी बने भारत-जापान

“

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया।

प्रेरणा

जुनून की शक्ति: जब साधारण प्रयास असाधारण सफलता बन जाते हैं

सफलता कभी भी केवल भाग्य का खेल नहीं होती। यह निरंतर परिश्रम, सीखने की इच्छा, धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम होती है। संसार के अधिकांश महान व्यक्तियों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति छोटे-से-छोटे अवसर को भी पूरे मन से अपनाता है, वही एक दिन बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हों, यदि मन में सीखने की आग और आगे बढ़ने का साहस हो, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने अपभवां के बीच रहते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से पूरी दुनिया को नई दिशा दी। ऐसे ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे माइकल फेराडे, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि निरंतर सीखने और काम करने की आदत से प्राप्त होती है। माइकल फेराडे का जन्म एक अत्यंत साधारण किसान में हुआ था। आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। बचपन से ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की सहायता करने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। लंदन की एक छोटी-सी पुस्तक बांधने की दुकान में उन्हें नौकरी मिली। उनका काम पुस्तकों की किले बांधना, पुराने पन्नों को ठीक करना, ग्राहकों की विविध व्यवस्थित करना और दुकान की साफ-सफाई करना था। देखने में यह एक सामान्य नौकरी थी, लेकिन फेराडे के लिए यह जान के विशाल संसार का द्वार बन गई।

दुकान में प्रतिदिन अनेक प्रकार की पुस्तकें आती थीं। इनमें साहित्य, इतिहास, दर्शन और विज्ञान से जुड़ी पुस्तकें भी होती थीं। अधिकांश कर्मचारी केवल अपना काम पूरा करने तक सीमित रहते थे, लेकिन फेराडे की सोच अलग के समाज, धर्म, संगीत, नृत्य और जीवनशैली की कहानी कहती हैं। यहां की नक्कशी इतनी सूक्ष्म और आकर्षक है कि एक-एक आकृति को देखकर कलाकारों की कल्पनाशक्ति और कौशल देखने को मिलता है। यह नगर केवल धार्मिक कलाओं की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों से जुड़े प्रसंगों को पथरों पर जीवंत रूप में उकेरा गया है। इस नगर का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कैलाशनाथर मंदिर माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर पल्लव शासकों की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का निर्माण विशाल बलुआ पथरों से किया गया है और इसकी दीवारों पर शिव के विभिन्न रूपों के साथ अनेक देवी-देवताओं की अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर का शत वातावरण धार्मिक प्रेरणा का प्रतीक है। यहां शीव, वैष्णव और शक्त परंपराएं समान सम्मान के साथ विकसित हुईं और आज भी उनकी परंपराएं जीवंत हैं। धार्मिक महत्व के साथ-साथ कांचीपुरम भारतीय कला और दर्शन का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में यहां अनेक गुरुकुल, वेद विद्यालय और मठ संचालित होते थे। संस्कृत, तमिल साहित्य, वेद, उपनिषद्, ज्योतिष, गणित और इसके नीचे माता पार्वती ने भगवान शिव की

थी। जब भी विज्ञान से संबंधित कोई पुस्तक उनके हाथ लगती, वे काम समाप्त होने के बाद उसके कुछ पन्ने प्थानपूर्वक पढ़ते। कई बार वे उन कठिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को बार-बार पढ़ते, समझने का प्रयास करते और अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर खोजते। औद्योगिक शिक्षा सीमित होने के बावजूद उनकी जिज्ञासा असीम थी, वे मानते थे कि यदि सीखने की इच्छा सच्ची हो, तो पुस्तकें सबसे बड़ा उपहान नहीं हूआ। कई दिनों तक वे उन नेट्स को व्यवस्थित रूप से लिखते रहे। उन्होंने उन्हें सुंदर ढंग से एक पुस्तक का रूप दिया, क्योंकि पुस्तक बांधने का कार्य वे पहले से जानते थे। इसके साथ उन्होंने एक अमूल्य विमल पत्र लिखा, जिसमें केवल इतना कहा कि वे विज्ञान सीखना चाहते हैं और यदि उन्हें कोई अवसर मिले तो वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे। प्रभु भगने के बाद कई सप्ताह तक कोई उत्तर नहीं

आया। अधिकांश लोग ऐसी स्थिति में निराश हो जाते और मान लेते कि उनका प्रयास व्यर्थ चला गया। लेकिन फेराडे ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे पहले की तरह अपना कार्य करते रहे और स्वयं अध्ययन जारी रखा। उनके भीतर यह विश्वास था कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन अचानक संदेश आया कि हमरी डेवी उनसे मिलना चाहते हैं। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर था। जब वे डेवी से मिले, तो उन्होंने फेराडे द्वारा तैयार किए गए नेट्स को देखा। नेट्स की साफ-सुथरी प्रस्तुति, विषय की समझ और सीखने की तीव्र इच्छा ने डेवी को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने समझ लिया कि यह युवक केवल नौकरी नहीं चाहता, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित है। कुछ समय बाद डेवी की प्रयोगशाला में सहायक का एक छोटा-सा पद खाली हुआ। उन्होंने फेराडे को यह अवसर दे दिया। यह कोई बड़ा वैज्ञानिक पद नहीं था। उनका काम प्रयोगशाला की गणिशायें साफ करना, उपकरणों को व्यवस्थित रखना, रसायनों को सही स्थान पर रखना और वैज्ञानिकों की सहायता करना था। बहुत से लोग ऐसे कार्य को महत्वहीन समझते, लेकिन फेराडे ने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख माना। वे हर उपकरण को ध्यान से देखते, हर प्रयोग को समझने का प्रयास करते और वैज्ञानिकों से लगातार सीखते रहते। उन्होंने कभी छोटे कार्य को छोटा नहीं समझा। उनके लिए प्रयोगशाला का प्रत्येक दिन एक विद्यालय था और प्रत्येक प्रयोग एक नया पाठ। वे जिज्ञाता काम करते, उससे कहीं अधिक सीखते। धीरे-धीरे उनकी वैज्ञानिक समझ इतनी अवसर मिले तो वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे। प्रभु भगने के बाद कई सप्ताह तक कोई उत्तर नहीं

स्तर पर किया जाता था। कई महान संतों, दर्शनियों और विद्वानों ने इस भूमि पर रहकर भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया। यही कारण है कि कांचीपुरम को केवल मंदिरों का शहर नहीं, बल्कि ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन की भूमि भी कहा जाता है। आज जब अधिकांश महानगरों में भागदौड़, प्रदूषण और तनाव जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, तब कांचीपुरम जैसी जगह मन को अद्भुत शांति प्रदान करती है। यहां सुकह मंदिरों की चट्टियों की मधुर ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, धूप और चंदन की सुगंध तथा भक्तों की श्रद्धा से भरा वातावरण एक अलग ही अनुभव कराता है। यहां आने वाले अनेक लोग बताते हैं कि शहर में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो मन को भीतर तक शांत कर देती है। कांचीपुरम की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय धम गया हो। यहां आज भी पारंपरिक जीवनशैली, पुराने मकान, छोटे-छोटे बाजार और मंदिरों से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। स्थानीय लोग अपनी परंपराओं को आज भी पूरे सम्मान के साथ निभाते हैं। यहां आने वाले पर्यटक दक्षिण भारतीय संस्कृति, संगीत, नृत्य और धार्मिक परंपराओं को बेहद करीब से देख सकते हैं। यदि कांचीपुरम का नाम लिया जाए और कांचीवरम सिल्क साड़ियों का उल्लेख न हो, तो यह चर्चा अधूरी मानी जाएगी। यह नगर विश्व प्रसिद्ध कांचीवरम रेशमी साड़ियों

ने उन्हें विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वर्षों की अथक मेहनत के बाद माइकल फेराडे ने विद्युत और चुंबकत्व के क्षेत्र में ऐसे अद्भुत अनुसंधान किए, जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। विद्युतचुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत, विद्युत मोटर और जेनरेटर के मूल सिद्धांतों पर उनका कार्य आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला बना। आज दुनिया में बिजली उत्पादन करने के दौरान बिजली के शुरुआत एक साधारण पुस्तक बांधने वाले कर्मचारी के रूप में की थी। फेराडे का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सही दृष्टिकोण से मिलती है। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली या वे किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। उन्होंने हर परिस्थिति को अवसर में बदला। जहां दूसरे लोग केवल पुस्तक देखते थे, वहां फेराडे ज्ञान का भंडार देखते थे। जहां दूसरे लोग केवल नौकरी करते थे, वहां वे सीखने का अवसर खोजते थे। यही सौच उन्हें साधारण से असाधारण बना गई। आज के समय में भी यह प्रेरणा उतनी ही प्रासंगिक है। इंटरनेट, पुस्तकालय, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अनेक साधन हमारे सामने उपलब्ध हैं। फिर भी यदि सीखने के इच्छा नहीं हो, तो कोई संसाधन सफलता नहीं दिला सकता। दूसरी ओर, यदि मन में जिज्ञासा, मेहनत और धैर्य हो, तो सीमित साधनों के बावजूद व्यक्ति अपने लिए नई बह बना सकता है।

पहले Pakistan के रास्ते अरब सागर तक पहुंच बनाई, अब Bangladesh के सहारे बंगाल की खाड़ी पर लगी चीन की नजर

दक्षिण एशिया में चीन ने अब भारत की पूर्वी सीमा पर नया सामरिक दांव चल दिया है। पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंच बनाने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बाद बांग्लां चीन की नजर बंगाल की खाड़ी पर है। हम आपको बता दें कि चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ते हुए एक नए आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा है, जो यदि आकार लेता है तो भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह केवल व्यापार और परिवहन का मामला नहीं है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक नीति का विस्तार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस पहल को खुला समर्थन दिया। योजना के तहत चीन के गुन्गान प्रांत के कुन्मिंग को म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के चट्टीग्राम, काक्स बाजार और मोंगला बंदरगाहों से जोड़ने की बात है। सड़क, रेल, जलमार्ग और बहुरैलियम परिवहन नेटवर्क के जरिये यह गलियारा चीन को सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच दिला सकता है। चीन के राजदूत याओ वेन ने साफ कहा कि यह पहल किसी एक देश तक सीमित नहीं है और यदि अन्य देश चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। यह बयान सीधे भारत की ओर संकेत माना जा रहा है। दरअसल यह वही विचार है जिसे पहले बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारे के रूप में आगे बढ़ाया गया था, लेकिन भारत की आपत्तियों और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना को लेकर संदेह के कारण यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब चीन ने भारत को अलग रहते हुए तीन देशों वाला नया विकल्प सामने रख दिया है। बांग्लादेश इस परियोजना को आर्थिक अवसर के रूप में पेश कर रहा है। ढाका का दावा है कि इसमें व्यापार बढ़ेगा, बंदरगाह आधुनिक होंगे और चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों तक सीधे पहुंच मिलेगी। खास बात यह है कि मोंगला बंदरगाह से रेटेजि आर्थिक क्षेत्र को पहले भारत समर्थित परियोजना के लिए चिन्हित किया गया था, उसे बांग्लादेश की सरकार ने हटकर अब चीन दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद बेहद प्रसिद्ध है। इटली, डोसा, वड़ा, पोंगल, सोमपर, नारियल की चटनी, रसम और फिक्कर कौभी का स्वाद पर्यटकों को लंबे समय तक याद रहता है। यहां का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। यदि यात्रा की योजना बनाई जाए तो अमृत्सर से मार्च तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और मंदिरों में बिभिन्न धार्मिक उत्सवों की रौनक देखने को मिलती है। रथ यात्राएं, संगीत समारोह, नृत्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस शहर की भव्यता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन आयोजनों के दौरान कांचीवरम सिल्क साड़ियों की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है।

खराब है कि चीन समर्थित ऊर्जा परियोजनायों को भी हटाना पड़ा है। ऐसे में सड़क और रेल संपर्क का सपना फिलहाल जमीन पर उतरता नहीं दिखता। देखा जाये तो भारत के लिए इस प्रस्ताव को हल्के में लेना भारी भूल होगी। चीन की रणनीति साफ है। पश्चिम में पाकिस्तान के जरिये अगर सागर तक पहुंच और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश के जरिये बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बनाकर वह भारत को समुद्री और भू रणनीतिक दबाव में लाना चाहते हैं। यह पहल मलक्का जलमल्लमयार क्षेत्र में चीन की दीर्घकालिक नीति कोशिश का भी हिस्सा मानी जा रही है। यदि चीन को बंगाल की खाड़ी तक निष्ठा पहुंच मिलती है तो हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी नौसैनिक सक्रियता और बढ़ सकती है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ आर्थिक गलियारा नहीं, बल्कि चीन की समुद्री रेशम मार्ग नीति का विस्तार है। चीन के राष्ट्रपति, औद्योगिक क्षेत्रों और परिवहन नेटवर्क के जरिये दक्षिण एशिया में स्थायी प्रभाव स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान में ग्वادر बंदरगाह के बाद अब मोंगला, चट्टीग्राम और न्याक्काम्पू जैसे ठिकाने चीन की समुद्री रणनीति के नए स्तंभ बन सकते हैं। देखा जाये तो नई दिल्ली के सामने चुनौती दोहरी है। एक ओर उसे अपनी पूर्वीयार और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक प्रभुत्व बनाए रखना है, दूसरी ओर बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ विवसाय और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यदि भारत इस बदलते भू-रणनीतिक परिदृश्य को समय रहते नहीं समझता, तो दक्षिण एशिया में चीन की पकड़ और मजबूत हो सकती है। फिलहाल यह साधारण प्रस्ताव के स्तर पर है, लेकिन इसका संदेश बेहद स्पष्ट है। चीन दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का नया नक्शा तैयार कर रहा है, और भारत की पूर्वी सीमा अब उस भू-राजनीतिक मुकाबले का अगला मोर्चा बनने जा रही है।

पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल
डिजिटली मिश्रेट विशाल कोटेड लेमिनेटेड स्टीकर्स के पेट्रिंग एवं आपूर्ति के लिए अनुबंध कार्य
ई-निविदा सूचना सं. 03आयएम (एए)डीआई/03/ ई-निविदा 27 दिनांक: 01/07/ 2026
योग्य ठेकेदारों से निम्न कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सं. एच 442/19/विनाईल स्टीकर्स/1। कार्य का नाम: कोथिप डिग्री कांकरिया और अहमदाबाद BG की प्राथमिक ट्रेनों के लिए दो वर्ष की समयवधि के लिए रेलवे इन्फ्रान्स्ट्रक्चर नॉन्वेय बोर्डार्ड, बेन्ती (फैक्टर) बोर्डार्ड एवं कोथ पुराना/ क्रिकोपिया नंबर चलेट्स के लिए डिजिटली कोटेड विशाल कोटेड लेमिनेटेड स्टीकर्स के आपूर्ति करने तथा विपकाने के लिए अनुबंध कार्य। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 24,10,850.55/- (स्वयं चीनीस लासद हार आठ सो पचास और चवन पैसे केवल) बीड सुरक्षा: ₹ 48,200/- (स्वयं खुलासे इस्तेमाल हो दो सो केवल)। निविदा बंद होने पर कोथ पुराना की तिथि एवं समय: दिनांक: 23/07/2026 को 15:00 बजे निविदा बंद की जायेगी एवं दिनांक: 23/07/2026 को 15:30 बजे निविदा खोली जाणी। वेबसाईट निवर्तन नोटिस जारी का स्थान नई निविदा आमंत्रित करने प्राधिकारी के कार्यालय का पता: https://www.irps.gov.in व/या: कोथिप डिग्री अधिकारी का कार्यालय, कोथिप डिग्री-कांकरिया, गोमतीपुर रेलवे यार्ड, नगरी नील के पास, अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे)-380021. ADJ-086
हो कौ की करें:  Twitter.com/WesternRly



गुजरात

द सेमीकंडक्टर हब

सेमीकंडक्टर उद्योग बना
साणंद की नई पहचान



सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात ने रचा इतिहास



सेमीकंडक्टर सेक्टर में गुजरात ने लगभग **₹1.24 लाख करोड़** का निवेश आकर्षित किया है।



राज्य में **50,000** से अधिक **प्रत्यक्ष** एवं **अप्रत्यक्ष** रोजगार के अवसर सृजित होंगे।



सेमीकंडक्टर नीति घोषित करने वाला **गुजरात** देश का पहला राज्य।



धोलेरा SIR में 28 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन से भारत को नई औद्योगिक पहचान मिलेगी।



धोलेरा को **'सेमीकंडक्टर-रेडी'** स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।



IIT गांधीनगर में **₹194.21 करोड़** की लागत से संचालित **'SAMARTH'** पहल के अंतर्गत अगले **5 वर्षों** में **2,600 से अधिक विशेषज्ञ इंजीनियर** तैयार किए जाएंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। साणंद अब केवल गुजरात का ही नहीं बल्कि नए भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। -**हर्ष संघवी**, उपमुख्यमंत्री, गुजरात

सूरत नासिनगर विध्वंस घोटाले में कथित तौर पर संलिप्त छगनलाल मेवाड़ा ने अधिकारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नासीनगर में भूटिया परिवार के घर को गिराए जाने का मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, और गुजरात उच्च न्यायालय को अपमानित करने के सूरत नगर निगम के दुर्भावनापूर्ण इरादे का पर्दाफाश हो रहा है। सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि यह तोड़फोड़ किसके आदेश पर की गई थी? आज तक एसएमसी अधिकारियों या पुलिस विभाग के किसी भी उच्च अधिकारी ने इस सवाल का कोई उचित और सटीक जवाब नहीं दिया है।

तो पहला सवाल यह उठता है कि सेना को युद्ध के लिए कहाँ भेजा जाए? क्या यह निर्णय सेनापति को लेना चाहिए या सेना को? क्या सेनापति के आदेश या अनुमति के बिना कोई भी सेना कभी भी शत्रु राज्य पर हमला नहीं कर सकती? फिर यहाँ, सूरत नगर निगम के नगर आयुक्त को इस बात की जानकारी नहीं है कि सूरत के वेदरोद नासिर नगर नामक क्षेत्र में 150 से अधिक मिट्टी की ईंटों से बने मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं और निवासियों को बेघर कर दिया गया है? गुजरात उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में नगर आयुक्त ने कहा कि यह विध्वंस मेरी जानकारी के बिना किया गया था।

इसी तरह, शीर्ष पुलिस अधिकारी, यानी शहर के पुलिस आयुक्त, इस बात से अनभिज्ञ हैं कि एसओजी (विशेष अभियान समूह) के डीसीपी नाकुम, जो सीधे उनसे जुड़े हुए हैं और पुलिस आयुक्त के निर्देशों के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, स्वयं चुपचाप खड़े रहे और निवासियों को अपने घरों से बाहर आने का निर्देश देते रहे तथा विध्वंस करने वालों को संरक्षण प्रदान करते रहे। इस विध्वंस का मामला अब इतना पेचीदा हो गया है कि राज्य सरकार में बैठे भ्रष्ट नेताओं ने अपने प्रिय और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों को बचाने की चाल के तहत, शहर के पुलिस आयुक्त को उच्च न्यायालय में पेशी की तारीखों से पहले ही अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने डीसीपी नाकुम को अचानक



आईपीएस अधिकारी बनाकर और इन गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को पदोन्नति देकर स्थानांतरित करके गरीबों के गालों पर तमाचा मारकर “पाप” किया है। सूरत नगर निगम के जिन पांच कर्मचारियों को इन बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए निलंबित किया गया है, वे भी लुटेरे का नाम आज तक साफ न करने और असली अपराधी को बेनकाब न करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। चंदाल बिल्डरों के समूह, टॉरेंट पावर, एसएमसी और पुलिस द्वारा किए गए इस फर्जी विध्वंस कार्य को देखते हुए, आज मानसून के मौसम में 150 परिवार बेघर हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ कोरी बातें ही हुई हैं। कोई ठोस या स्पष्ट बात सामने नहीं आई है। मामला और भी पेचीदा इसलिए हो गया है क्योंकि इसे नगर पुलिस आयुक्त या नगरपालिका आयुक्त पेश कर रहे हैं। बारह दिनों तक कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हुआ, और अंत में बेतुके बचाव करके जनता की आंखों में धूल झाँकने का नाटक शुरू हो गया है।

एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस इलाके में तोड़फोड़ हुई है, वह किस जोन में आता है? राज्य सरकार अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि यह उतरी जोन है या मध्य जोन। फिलहाल निलंबित कर्मचारी घर पर आराम करेंगे। और जांच सालों तक चलती रहेगी। इतना ही नहीं, यह मानना भी मुश्किल है कि सूरत नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने अकेले ही यह सब किया है। इस पूरे घोटाले में सूरत नगर निगम आयुक्त से भी उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जरूरत है, तभी असली

दोषियों का पर्दाफाश होगा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निलंबित किए गए पांचों अधिकारियों ने एक महीने के दौरान कहा था कि वे वरिष्ठ अधिकारी का नाम उजागर करेंगे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने नाम नहीं बताया। क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी भी घबराए हुए थे। इसी वजह से उनका निलंबन तीन बार रद्द किया गया, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि आम तौर पर जब भी कोई तोड़फोड़ होती है, तो जिस पुलिस स्टेशन के अधिकारी की इमारत गिराई जानी होती है, उसका स्टाफ मौके पर मौजूद होता है। लेकिन इस बार खुद एसओजी के डीसीपी ने खड़े होकर तोड़फोड़ करवाई, जिससे साफ पता चलता है कि यह तोड़फोड़ बिल्डर लॉबी, टॉरेंट पावर और पुलिस के उच्च अधिकारियों व सूरत नगर निगम के बड़े अधिकारियों के इशारे पर की गई थी। इस तोड़फोड़ की एक और खासियत यह है कि अभी तक किसी भी बिल्डर या टॉरेंट पावर के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए निचले अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने के खेल में पुलिस कमिश्नर का रातोरात तबादला और बदनाम डीसीपी नाकुम को आईपीएस अधिकारी के पद पर पदोन्नति देना, ये सब कुछ शब्दों में बहुत कुछ बयां करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस मामले में कौन बेनकाब होगा।

छगनलाल मेवाड़ा का पत्रकारिता पर बढ़ते खतरों पर लेख, अनैतिक व्यवसायों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत पत्रकारिता जगत, जिसे विश्व का चौथा स्तंभ माना जाता है, वर्तमान में संकट में है। पत्रकारिता जगत से जुड़ा व्यक्ति पत्रकार होता है। उसका काम जनता की समस्याओं को आवाज देना, निडरता और साहस से प्रेस के माध्यम से जनता के साथ हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मौजूद बुराइयों में शराब और जुआ, अनैतिक व्यापार, नशीली दवाएँ, गांजा, चरस, मादक पदार्थ और अन्य ऐसे धंधे शामिल हैं जिन्होंने मानव जगत में तबाही मचा रखी है। ऐसे कृत्यों को उजागर करना एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार का कर्तव्य है।

समाज में चल रही अनैतिक गतिविधियों

को उजागर करना और पुलिस को इसकी जानकारी देना पत्रकारों का काम है। पत्रकार ही किसी स्थान पर हो रही अनैतिक गतिविधियों को कैमरे में कैद करते हैं या वीडियो के माध्यम से अपराधियों को बेनकाब करते हैं, और आम जनता को पीड़ा पहुंचाने वाले अपराधियों का पर्दाफाश करते हैं। इससे पुलिस और सरकार को प्रेस रिपोर्टों और समाचार चैनलों के माध्यम से उचित कार्रवाई करने और ऐसे अनैतिक कृत्यों को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या शराबखोरी, जुआ, अनैतिकता या किसी भी अन्य अवैध गतिविधि जैसी सामाजिक बुराइयों को उजागर करना

अपराध है? क्या पुलिस का ध्यान ऐसी गतिविधियों की ओर आकर्षित करने के लिए अखबार के माध्यम से रिपोर्ट प्रकाशित करना अपराध है? यदि रिपोर्ट प्रकाशित करना अपराध है, तो अखबार को कानूनी नोटिस भेजें और अदालत में मामला ले जाएँ, अदालत खुली है। लेकिन किसी पत्रकार पर हमला करना या उसके परिवार को डराना-धमकाना किस हद तक उचित है? और यदि किसी को लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है या समाज में हमारा अपमान हुआ है, तो उन्हें कानूनी तौर पर समाचार पत्र को नोटिस भेजना चाहिए। न्यायालय समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए खुला है।

नासिरनगर विध्वंस: पुलिस तैनाती, एसओजी तैनाती और मंजूरी पर सवाल उठे

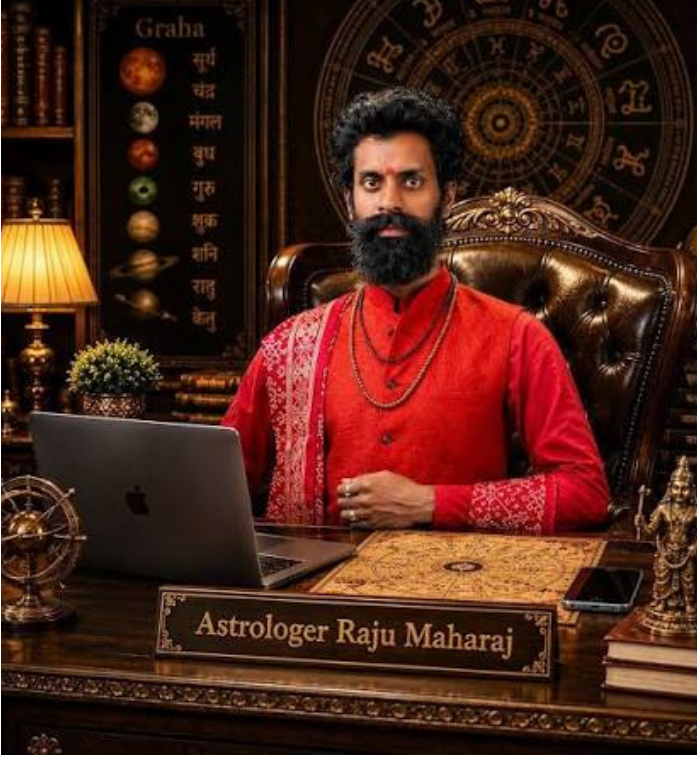
(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) जब पुलिस सुरक्षा के लिए आवेदन पुलिस आयुक्त के पास मंजूरी के लिए जाता है, तो क्या नासिर नगर विध्वंस की सुरक्षा संबंधी फाइल पुलिस आयुक्त तक पहुंची

है या नहीं? आम तौर पर, पुलिस सुरक्षा संबंधित विध्वंस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन द्वारा आवंटित की जाती है। तो नासिर नगर के लिए एसओजी की विशेष सुरक्षा की क्या आवश्यकता है?

अगर नगर आयुक्त को वाकई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने झूठे बयान क्यों दिए? केंद्रीय क्षेत्र के अधिकारी इतने मूर्ख नहीं हैं कि नगर आयुक्त या क्षेत्र प्रमुख को अनुमति के बिना इधर-उधर भागते फिरें।

नई दिल्ली में सूरत के ज्योतिषी राजू महाराज को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार मिला

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत सूरत के प्रसिद्ध और लोकप्रिय ज्योतिषी राजू महाराज को देश की राजधानी नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार मिला है। सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य शहरों में अनेक शिष्यों वाले राजू महाराज ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। उनके परामर्श और मार्गदर्शन से कई परिवार सुखमय जीवन जी रहे हैं। शांत और सरल स्वभाव के राजू महाराज से मिलने पर लोगों में खुशी और उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। उनके मार्गदर्शन और ज्योतिषीय शक्ति से लोगों के दुख-दर्द दूर होते हैं। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी का पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष, जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता भाई लाल बी. वैष्णव, उपाध्यक्ष छगनलाल मेवाड़ा, महासचिव सईदउद्दीन शेख, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, महासचिव श्यामभाई तैनिया, महासचिव रवि कुमार सुरती, कार्यकारी अध्यक्ष हसमुखभाई पटेल, अधिवक्ता और उद्योगपति डी.सी. सोलंकी (अंकलेश्वर), अधिवक्ता बिपिनभाई राठोड़ (ननसारी), अधिवक्ता और नोटरी अश्विनभाई वैष्णव, अधिवक्ता महेंद्र सोलंकी और अन्य ने



ज्योतिषी श्री राजू महाराज को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। राजू महाराज

की सुविधानुसार सूरत में जल्द ही एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा।

गुजरात सरकार का ऐतिहासिक किसानोन्मुखी निर्णय बिजली टावर तथा लाइन मुआवजे में भारी वृद्धि

► जंत्री के बजाय अब बाजार भाव से दोगुने दर पर मुआवजा दिया जाएगा।

► टावर बेस क्षेत्र की गणना में चारों ओर अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़ा गया, 765 केवी लाइन में 625 वर्गमीटर के बजाय 729 वर्गमीटर का मुआवजा दिया जाएगा

► भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य तय करने के लिए ‘मार्केट रेट कमेटी’ (एमआरसी)

का गठन होगा; किसान प्रतिनिधियों को मिलेगा स्थान

► पूर्व में तीन चरणों में भुगतान होता था, अब एक साथ शुरुआत में ही 100 प्रतिशत भुगतान

उदाहरण - 1		
	गुजरात सरकार के प्रस्ताव दि: 01.03.2024 के अनुसार	प्रस्तावित (1 बीघा = 30 लाख के अनुसार)
	DLVC दर के अनुसार (टावर के लिए – 979 रुपए प्रति वर्गमीटर) (RoW कॉरिडोर के लिए – 761 रुपए प्रति वर्गमीटर	मार्केट रेट कमिटी (MRC) के अनुसार (1853.29 रुपए प्रति वर्गमीटर)
टावर के चार पायों (आधारों) से घिरा क्षेत्र	6.11 लाख (625 वर्गमीटर)	27.02 लाख (729 वर्गमीटर)
RoW कॉरिडोर	12.74 लाख (25% RoW)	37.25 लाख (30% RoW)

उदाहरण 2		
	गुजरात सरकार के प्रस्ताव दि: 01.03.2024 के अनुसार	प्रस्तावित (1 बीघा = 20 लाख के अनुसार)
	DLVC दर के अनुसार (टावर और RoW कॉरिडोर के लिए – 382 रुपए प्रति वर्गमीटर)	मार्केट रेट कमिटी (MRC) के अनुसार (1235.53 रुपए प्रति वर्गमीटर)
टावर के चार पायों (आधारों) से घिरा क्षेत्र	2.38 लाख (625 वर्गमीटर)	18.00 लाख (729 वर्गमीटर)
RoW कॉरिडोर	6.39 लाख (25% RoW)	24.83 लाख (30% RoW)



गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल किसानों के नेतृत्व में तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया ने किसानों के साथ चर्चा, विचार-विमर्श एवं परामर्श करके तथा किसानों के आर्थिक हित को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण एवं उदार निर्णय लिया है। खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन तथा बिजली टावर स्थापित किए जाने के बद्दले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को उनकी भूमि का उचित एवं बाजार आधारित मुआवजा

मिलेगा। किसानों के खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन के लिए अब तक खेत में बिजली पोल-खंभे अथवा लाइन डालने के बदले किसानों को जंत्री की दोगुनी दर (200 प्रतिशत) के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाता था। इस संबंध में विभिन्न किसान संगठनों से प्राप्त प्रस्तुतियों के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा बड़ा सुधार करते हुए जंत्री आधारित नहीं, बल्कि भूमि के प्रचलित बाजार भाव (मार्केट रेट) के दोगुने मूल्य का भुगतान करने का किसान-हितैषी निर्णय किया गया है। इसके अतिरिक्त; अब तक खेत में स्थापित किए जाने वाले बिजली टावर के बेस (नींव) क्षेत्र के वास्तविक माप

के अनुसार ही मुआवजा दिया जाता था। अब से किसानों के लाभ के लिए टावर के बेस क्षेत्र की प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़कर अधिक मुआवजा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए; 765 केवी लाइन में पहले 625 वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जिसे अब से प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक मीटर जोड़ते हुए बढ़ाकर 729 वर्गमीटर के हिसाब से दिया जाएगा। पूर्व में जमीन मालिकों को मुआवजे के संबंध में फाउंडेशन चरण में 40 प्रतिशत, इंरेक्शन के समय 40 प्रतिशत तथा तार बिछाने के बाद 20 प्रतिशत के अनुसार भुगतान किया जाता था। अब इसके स्थान पर जमीन मालिकों

को एकमुश्त तथा कार्य शुरू होने से पहले ही 100 प्रतिशत मुआवजा देने का निश्चय किया गया है। किसानों की भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य तटस्थ एवं पारदर्शी ढंग से निर्धारित हो सके; इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाजार दर समिति (एमआरसी) का गठन किया जाएगा। विशेष बात यह है कि इस समिति में प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि तथा किसानों के अधिकृत मार्केट वैल्यूअर को भी स्थान दिया जाएगा, जिससे किसानों के साथ अन्याय न हो। मार्केट रेट निर्धारित करने वाली समिति में कलेक्टर, भूमि मालिकों के प्रतिनिधि तथा ट्रॉंसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

दूसरी ओर; बिजली लाइन के राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए एमआरसी द्वारा निर्धारित हुए बाजार मूल्य के आधार पर क्षेत्रानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत और महानगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस निर्णय में उदारता दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पहले पुराने दाम के अनुसार मुआवजा प्राप्त कर लिया है, परंतु बिजली लाइन का कार्य अभी प्रगति पर है; ऐसे सभी किसानों को भी इस नीति का लाभ देय होगा।

